- 19th Year
- Issue: 221
- 16.12.2025 (TUESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

भाजपा हेडक्वार्टर में नितिन नबीन ने संभाली कार्यकारी अध्यक्ष की कमान, अमित शाह-जेपी नड्डा भी रहे मौजूद

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुज़्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। राजधानी में भाजपा मुज़्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, रवि शंकर प्रसाद और दिल्ली की मुज़्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई नेता पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे।

45 वर्षीय नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बिहार से पांच बार विधायक रह चुके नबीन वर्तमान में राज्य के सड़क निर्माण मंत्री हैं और इससे पहले शहरी विकास एवं आवास एवं विधि विभाग जैसे विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र नबीन के पास प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ पार्टी के भीतर एक लंबा संगठनात्मक करियर भी है। वे आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले एएनआई से बात करते हुए नबीन ने बिहार और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर इस पद तक पहुंचने का श्रेय उनके आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पा रहा है। नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन को भी स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें यह जिज़्मेदारी सौंपी। पांच बार विधायक रह चुके नबीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार सरकार में दो बार मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। बिहार में मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और छज़ीसगढ़ में पार्टी प्रभारी के रूप में उनकी भूमिका वास्तव में उत्कृष्ट रही है और उनके प्रभावी संगठनात्मक नेतृत्व की झलक मिलती है। भाजपा संसदीय बोर्ड ने इस पद के लिए नवीन को चुना है। वर्तमान में, वे बिहार में पीडज़्लू मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक हैं।

कांग्रेस रैली में हुआ पीएम मोदी का अपमान! रास में जेपी नड्डा की मांग, सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए माफी

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी को कल कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कल की कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। यह कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें कहना निंदनीय है। सोनिया गांधी जी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच, लोकसभा में किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि कांग्रेस की एक रैली में कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए। उन्होंने इसे भारत के लिए बेहद दुखद समय बताया कि कांग्रेस की पुरानी पार्टी ऐसे शज़्दों का इस्तेमाल कर रही है। रिजिजू ने कहा, रैली में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए गए। कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया।

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद भले ही हों, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में बोलते समय हमें संयम बरतना चाहिए। एनसीपी (एसपी) नेता जयंत पाटिल ने कहा कि इस तरह के नारे लगाना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह (नरेंद्र मोदी) प्रधानमंत्री हैं। रविवार को भाजपा पर विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का विरोध करने के लिए आयोजित %वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीना ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कबर नारा लगाया।बाद में जब पत्रकारों ने उनसे इस टिप्पणी के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि वह केवल वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को व्यक्त कर रही थीं।

विज़ मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले असम के सीएम, विकास और कल्याणकारी पहलों पर हुई चर्चा

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): असम के मुज़्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को केंद्रीय विज़ मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। एक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में असम के आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास और जन कल्याणकारी पहलों से संबंधित कई विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा का मुज़्य बिंदु असम की विकास गति को और तेज करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को मजबूत करना था। मुज़्यमंत्री ने असम के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय विज़ मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और राज्य के लोगों की समग्र प्रगति और कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बाद में, पूर्व

ट्विटर (ङ्क) पर मुज़्यमंत्री शर्मा ने लिखा, आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय विज़ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात करके सज़्मानित महसूस कर रहा हूं। हमने असम के विकास और हमारी जनता के कल्याण से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।

मुज़्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मैंने हमारी विकास यात्रा में उनके निरंतर समर्थन के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले रविवार को, मुज़्यमंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान, मुज़्यमंत्री शर्मा ने राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी।

मुज़्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को असम आने और राज्य के परिवर्तन और हालिया विकास प्रगति को देखने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने इस भाव की सराहना की और 30 मिनट की बैठक के दौरान मुज़्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की।

एस. जयशंकर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने इजराइल का दौरा करेंगे

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार को इजराइल पहुंचेंगे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके। उनकी यात्रा से कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी से बातचीत की थी जिस दौरान दोनों नेता बहुत जल्द मिलने पर सहमत हुए। पर्यटन मंत्री हाइम काट्ज़, अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बरकत, कृषि व खाद्य सुरक्षा मंत्री

अवी डिज़्टर और विज़ मंत्री बेज़ालेएल स्मोट्रिच इस साल पहले भारत गए थे। यह दौरे इसलिए हुए ज़्योंकि भारत और उनके देश के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है और दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए और फिर पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा के दौरान एक संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए गए, जो आगे चल कर एफटीए का आधार बनेगा।

एमजीएनआरईजीए को लेकर शुरू हुई सियासत, खरगे बोले- नाम बदलने का सड़क से लेकर संसद तक करेंगे कड़ा विरोध

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): सोमवार को संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) को बदलने वाले विधेयक के पेश होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सज़ारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए इसे एमजीएनआरईजीए को खत्म करने के लिए भाजपा-आरएसएस की साजिश बताया। एज़्स पर एक पोस्ट में, खरगे ने आरोप लगाया कि यह कदम इस प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने और अंतत: खत्म करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।खरगे ने एज़्स पर पोस्ट किया कि यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का मामला नहीं है। यह

एमजीएनआरईजीए को खत्म करने के लिए भाजपा-आरएसएस की साजिश है। संघ की शताज़्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि वे लोग कितने खोखले और पाखंडी हैं जो मोदी जी की तरह विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं।

गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही एमजीएनआरईजीए पर हमला करती है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, इस बात पर जोर देते हुए खरगे ने कहा कि पार्टी संसद के अंदर और बाहर, गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ ऐसे किसी भी फैसले का विरोध करेगी।

पोस्ट में आगे कहा गया कि कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के ऐसे किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी जो गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ है। हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सज़ा में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे।

झारखंड के सीएम ने ऑस्ट्रेलिया के राजदूत से निवेश और खदान सुरक्षा पर चर्चा की

रांची १५/१२ (संवाददाता): झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ओएएम से राज्य में निवेश की संभावनाओं और खदान सुरक्षा पर चर्चा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया।

'फर्स्ट सेक्रेटरी' टॉम सैंडरफोर्ड और अन्य अधिकारियों के साथ ग्रीन मुज़्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सोरेन से मिले। सोरेन ने उच्चायुक्त को झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और राज्य सरकार की निवेश नीतियों के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राज्य को श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के अपने दृष्टिकोण को भी साझा किया और साझेदारी को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

ग्रीन ने कहा कि खनन को लेकर झारखंड और ऑस्ट्रेलिया में काफी समानताएं हैं। उन्होंने खदान सुरक्षा और सुरक्षित खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया में उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रकाश डाला। राजदूत ने सोरेन को ऑस्ट्रेलिया आने का निमंत्रण भी दिया।

अमीर प्रदूषण फैलाते हैं, गरीब मार झेलते हैं-सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में वह प्रभावी आदेश पारित करेगा, जिन्हें लागू किया जा सकेगा। भारत के मुज़्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संकट के मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो एमिकस ज़्यूरी के रूप में बेंच की सहायता कर रही हैं। बेंच के समक्ष यह मामला उठाते हुए कहा कि हालांकि निवारक उपाय लागू हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनका खराब कार्यान्वयन ही मुज़्य समस्या

है। उन्होंने कहा कि जब तक यह अदालत कोई निर्देश नहीं देती, अधिकारी पहले से मौजूद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। इस पर पीठ ने कहा, यह मामला बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आएगा। इस पर सुनवाई अवश्य होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समस्या को जानते हैं और हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। मुज़्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि प्रदूषण की मार सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अज़्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। एमिकस ज़्यूरी अपराजिता सिंह ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि गरीब मजदूर इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। महानगरों में लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है और वो गंभीर वायु प्रदूषण के बावजूद उसमें बदलाव नहीं लाना चाहते। लेकिन गरीबों का ज़्या होगा। एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित एक आवेदन का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व आदेशों के बावजूद स्कूलों में बाहरी खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राज्य अदालत के आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे... पिछले महीने आदेश पारित किया गया था कि दिसंबर-जनवरी में खेल आयोजन नहीं होंगे, इसके बावजूद ऐसे आयोजनों के लिए आदेश पारित किए जाने के बाद भी, उन्होंने आदेश को दरकिनार करने के तरीके खोज लिए हैं। मुज़्य न्यायाधीश ने जवाब दिया हम समस्या को जानते हैं और आइए हम ऐसे आदेश पारित करें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें सज़्ती से लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली होती है।

सिंह ने कहा कि गरीब मजदूर सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, और उन्होंने आगे कहा कि जीआरएपी-ढ्ढङ्क उपायों के लागू होने से निर्माण मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं। मुज़्य न्यायाधीश ने कहा कि हम केवल प्रभावी आदेश ही पारित करेंगे, कुछ निश्चित निर्देश हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है, लोगों को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढलना होगा। उन्हें अपनी जीवनशैली में बदलाव करना होगा... महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली होती है जिसे वे नहीं बदलते, समस्या धनी वर्ग के साथ उत्पन्न होती है, गरीब वर्ग प्रभावित होता है।

विविध समाचार

पीएम नरेन्द्र मोदी को अपशज़्द कहने पर संसद में हंगामा, नड्डा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का यह आखिरी सप्ताह है। आज भी दोनों सदनों में सामान्य रूप से कामकाज देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने संसद में आपज़ि जताई। खुद जेपी नड्डा ने इसको लेकर सोनिया गांधी से माफी की मांग की।

राज्यसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा हुई। लोकसभा में अनुदान के लिए पूरक मांगें (2025-26, पहला बैच)% पर चर्चा हुई। राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं विकास विधेयक, 2025 को प्रस्तुत किया।

राज्यसभा में सोमवार को सदन के नेता जे पी नड्डा ने एक दिन पहले कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध लगाए गए नारों की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने को कहा। उच्च सदन की बैठक शुरू होते ही नड्डा ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि कल यहां कांग्रेस की रैली में ''मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी'' के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा, ''इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और आदरणीय सोनिया गांधीजी को पूर देश से माफी मांगनी चाहिए।'' लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगनी चाहिए।

सरकार 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) को निरस्त करने और इस संबंध में एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक लेकर आ सकती है। नए विधेयक का नाम 'विकसित भारत- रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025' होगा।

विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांटी गई हैं। विधेयक का उद्देश्य '' 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ''ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जिसके तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के

वयस्क सदस्यों को हर विज्ञ वर्ष में 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्व-शासन वाले संस्थान बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, 2025 विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह शिक्षण संस्थानों की स्वायज़ता का उल्लंघन करता है और उनकी स्वतंत्रता का क्षरण करता है।

राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया वहीं भाजपा के बारे में कहा कि उसकी जान ईवीएम में बसती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई राज्यों में वोट चोरी होने का प्रमाण दिया है लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिहार में सरकार के कदमों पर रोक नहीं लगायी गयी जबकि कई राज्यों में सरकार के कदमों पर रोक लगा दी गयी।

कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने सोमवार को मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरी तरह विफल होने का दावा किया तथा आर्थिक विकास दर मापने की नयी पद्धति पर सवाल खड़े किये। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें-प्रथम बैच और संबंधित विनियोग (संज़्याक 4) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये का न्यूनतम स्तर पर जाना भारतीय अर्थव्यवस्था की बदहाली और कुशासन को दर्शाता है।

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों को आगाह किया कि यदि वे 'वोटी चोरी' के आरोपों को जारी रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर दोषारोपण कर मतदाताओं के मन में सन्देह पैदा करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एयरसेवा वेब पोर्टल और ऐप से संबंधित प्रश्नों का उज़र दिया। उन्होंने सदन को सूचित किया कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (डीजीसीए) ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें विभिन्न स्थितियों, जैसे उड़ान में देरी, सामान खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में यात्रियों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यसभा में सोमवार को कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने दलबदल विरोधी कानून में सुधार की मांग करते हुए जनादेश का सज़्मान किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। चुनाव सुधारों पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के के.आर. सुरेश रेड्डी और मार्क्सवादी कज़्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास ने कहा कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा न करना मतदाता के साथ शाज़्दिक रूप से धोखाधड़ी के समान है और यह दलबदल चुनावों की शुचिता पर सवाल खड़े करता है।

प्रियंका गांधी से ज़्यों मिलने पहुंच गए प्रशांत किशोर? दिल्ली में 2 घंटे तक गुपचुप मुलाकात के ज़्या है मायने?

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में जन सूरज पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं में छा गए हैं। किशोर ने हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई अटकलें लगने लगी हैं। प्रशांत किशोर का गांधी परिवार से रिश्ता नया नहीं है। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद, किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने की योजना प्रस्तुत की थी।

अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सशक्त कार्य समूह का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों ने बताया कि बैठक लगभग दो घंटे तक चली, हालांकि दोनों पक्षों ने इसके महत्व को कम आंकने की कोशिश की है और इसे एक नियमित बातचीत बताया है। किशोर की जन सूरज पार्टी की करारी चुनावी हार के बाद यह मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही और 236 उज़्मीदवारों की जमानत जज़्त हो गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा और उसने 61 सीटों में से सिर्फ छह सीटें जीतीं। किशोर की प्रियंका गांधी से बातचीत ने उनकी राजनीतिक रणनीति में संभावित बदलाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस से स्पष्ट दूरी बनाए रखी थी। किशोर का कांग्रेस नेतृत्व से जुड़ाव 2021 से शुरू हुआ, जब उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) छोड़ दिया था। अप्रैल 2022 में, किशोर ने सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित एक बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष एक विस्तृत पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उपस्थित थे। उस समय, किशोर को पार्टी के प्रस्तावित卐सशक्त कार्य समूह卐 में भूमिका की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि कांग्रेस को सीमित संगठनात्मक भूमिकाओं के बजाय संरचनात्मक सुधारों और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है। इस असहमति के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए, और किशोर बाद में पार्टी के एक मुखर आलोचक के रूप में उभरे।

हालांकि, प्रियंका गांधी के साथ चुनाव के बाद हुई मुलाकात से संकेत मिलता है कि संवाद के रास्ते खुले हैं। इंडियन एज़्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चर्चा बिहार की राजनीति, विपक्ष की रणनीति और भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं पर केंद्रित थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये बातचीत किसी औपचारिक सहयोग में तज़्दील हो पाएगी या नहीं।

राममंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी ने जताया दुख

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से अयोध्या, संपूर्ण संत समुदाय और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। डॉ. रामविलास दास वेदांती मध्य प्रदेश के रीवा जिले के दौरे पर थे। बुधवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉज़्टरों ने उनके इलाज के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदुख जताते हुए एज़्स पर लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका

त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

उपमुज़्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉ. राम विलास दास वेदांती एक सच्चे नायक थे, और हमने पूर्व सांसद के रूप में उनकी सेवा को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वे एक दृढ़ और साहसी नेता थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं... राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कई संघर्षों में हम उनके साथ थे, और आज यह समाचार सुनकर हमें गहरा दुख और पीड़ा हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।

उपमुज़्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों और समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति दें। उनका संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित था। उन्होंने राष्ट्र और राज्य की सेवा भी की... लोक सेवा में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे, और वे हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े रहे, गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे... उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया, और अयोध्या धाम से निरंतर जुड़े रहे।

59 लाख वोटर हटे, भवानीपुर में 45 हज़ार फर्जी मतदाता! समझिए बंगाल का पूरा एसआईआर

कोलकाता १५/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद आंकड़े आ गए हैं कि कितने वोटर कटे हैं। यह पहली रिपोर्ट है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जारी पहली रिपोर्ट के अनुसार 59 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं। हालांकि जब तक 16 तारीख को पहला ड्राज़्ट नहीं आ जाताष नई वोटर लिस्ट का 16 दिसंबर को ड्राज़्ट पज़्लिकेशन होगा। इसके बाद लोगों की आपज़ियां और दावे लेने का दौर शुरू होगा। चुनाव आयोग बकायदा ऑफिशियल जारी करेगा। लेकिन जो चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार 59 लाख वोट कट गए हैं। साउथ 24 परगना में। विधानसभा पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चौरंगी विधानसभा है। वहां 75,000 वोट कट गए हैं। 75,000 वोट एक विधानसभा में कट गए हैं। इसके अलावा जहां पे ज्यादा कटे हैं उसमें कोलकाता की सीट है, हुगली की सीट है, जोरापाखी एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां कटा है। अब जिन विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपकी रुचि होगी, जैसे ममता बनर्जी की भवानीपुर। ममता बनर्जी की भवानीपुर में 44787 करीब-करीब 45,000 वोटर कट गए हैं। शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम यहां कुल वोटरों की संज़्या थी 21,000 इसमें से 10,000 कुछ वोट कटे हैं। यह एक करोड़ वोटर वह बताए जा रहे हैं जिनका पश्चिम बंगाल में 2002 में हुए एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट में नाम मैच नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा इतनी बढ़ी संज़्या में वोटरों में कुछ के बाहरी होने का भी संदेह है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संज़्या में सभी बांग्लादेश, ज़्यांमार या अन्य किसी देश के नागरिक हों। इन वोटरों की पुरानी एसआईआर वाली लिस्ट से मैपिंग नहीं हो पाई है। इसलिए इन्हें नोटिस देकर इनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सीईओ ऑफिस से दो दिन पहले नई वोटर लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी साझा की गई थी। जिसमें बताया गया था कि बंगाल की बन रही नई वोटर लिस्ट के ड्राज़्ट पज़्लिकेशन में स्र लाख से अधिक चुक वोटरों के नाम कटे हुए होंगे। यह वोटर वो हैं। जो मर चुके हैं, स्थायी रूप से बंगाल छोड़ चुके हैं और डुप्लीकेट वोटर होने समेत अन्य कई तरह की विसंगतियों वाले वोटर पाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में सबसे अधिक वोट कट सकते हैं। यहां 44 हजार से अधिक वोट डिलीट होना बताया जा रहा है। जबकि उज़र और दक्षिण 24 परगना से 16 लाख से अधिक वोट कटे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि 24 लाख से अधिक ऐसे वोटरों का भी पता लगा है। जिनके छह या इससे अधिक बच्चे हैं। इनमें माता-पिता और बच्चों की उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं है। 85 लाख से अधिक वोटरों के पिता के नाम और अन्य कंटेट में गलतियां मिली है।

बीजेपी सांसद के साथ शशि थरूर की सेल्फी, ज़्या होने वाला है बड़ा खेल?

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता):भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ ज़्लाइट से ली गई एक सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की।

हालांकिए जिस चीज ने ध्यान खींचाए वह था भाजपा नेता का विचित्र कैप्शनए ष्मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे यह कहने पर शरारती कहा कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं।ष् यह सेल्फी थरूर की रूस.यूक्रेन के मामले में भारत के रुख पर की गई टिप्पणी के कुछ दिनों बाद आई हैए जिसने भाजपा को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया।

भाजपा ने रूस.यूक्रेन युद्ध से निपटने के लिए भारत की प्रशंसा करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सूझबूझ का समर्थन बताया।

वरिष्ठ भाजपा नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने थरूर की इस स्वीकारोक्ति का स्वागत किया कि युद्ध पर सरकार के तटस्थ रुख की उनकी शुरुआती आलोचना गलत थी। इसे ष्देर आए दुरुस्त आएष् का मामला बताते हुए प्रसाद ने कहाए ष्मोदी सरकार ऐसे फैसले लेती है जो भारत के सर्वोज़म हितों को पूरा करते हैं। अगर कांग्रेस के अन्य नेता भी इसे स्वीकार करते हैंए तो यह फायदेमंद होगा।ष्

भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जोर देकर कहा कि भारत की कूटनीतिक क्षमता वैश्विक मामलों को समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों के साथ गर्मजोशी से जुड़ने की मोदी की क्षमता भारत की संतुलित विदेश नीति को दर्शाती है। विदेश राज्य मंत्री रह चुके थरूर ने मंगलवार को माना था कि भारत के दृष्टिकोण ने मोदी को रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अनुमति दी।

भारत स्वदेशी ड्रोन.रोधी समाधान की खोज के बहुत करीब-शाह

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता):केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि भारत एक पूर्ण एवं स्वदेशी ड्रोन.रोधी समाधान की खोज के बहुत करीब है और यह काम छह महीने के भीतर हो जाएगा। गृह मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहाए ष्हम ड्रोन.रोधी पूर्ण समाधान पाने के बहुत करीब हैं। हमने छह प्रयोग किए हैंए मुझे उज़्मीद है कि छह महीने के भीतर हमारे पास ड्रोन.रोधी स्वदेशी समाधान होगाए जो ष्मेक इन इंडियाष् का प्रतीक होगा।ष गृह मंत्री ने कहा कि अफीम की खेती पर नज़र रखने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहाए ष्हमने अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए ड्रोनए उपग्रह और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 14000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 23ए000 किलोग्राम ष्सिंथेटिकष् दवाओं को नष्ट किया गया है। उन्होंने कहाए ष्अफगानिस्तान से श्रीलंका तक नशीली दवाएं भेजी जाती हैंए वे ;विपक्षी सदस्यद्ध पूछते हैं कि गुजरात में ड्रग्स ज़्यों पकड़ी जा रही हैण्ण्ण् इसे अन्य राज्यों में भी पकड़ा जाना चाहिए। हमने वचन दिया है कि किसी भी तरह के मादक पदार्थ को भारत में आने या यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित धन का उपयोग आतंकवादी घटनाओं के लिए किया जाता है.

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

लेना है विदेश में एजुकेशन इन बातों का ध्यान रखें

उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे इसके लिए फोकस्ड तैयारी करें। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे इसके लिए फोकस्ड तैयारी करें। इस बारे में यहां उपयोगी सलाह दे रही हैं आदित्य बिड़ला वर्ल्ड अकेडमी की हेड करियर गाइडेंस काउंसलर।

विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना कब से शुरू कर देना चाहिए?

आठवीं से ही। हम उनसे कहते हैं कि वे अपने करियर के बारे में सोचना और उस पर काम करना शुरू कर दें। कौन-से विषय वहां तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे, कौन-से कॉलेज में पढ़ाई करनी है, ये सारे फैसले बाद में लेने होंगे। यह जरूरी नहीं कि आप विदेशी यूनिवर्सिटीज की ओर ही देखें। भारत में भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। जरूरी यह है कि आप फोकस्ड रहें।

क्या एक साल का गैप लेना ठीक है, जो आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है?

गैप ईयर का परसेप्शन बदल रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई विद्यार्थी कैसे साल बिताता है। गैप लेने के बाद जिनकी एप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, वे अकेडेमिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपने सफर के दौरान वे कई तरह की इंटर्नशिप भी करते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज भी यही देखती हैं। वे जानना चाहती हैं कि विद्यार्थी कैसे अपने समुदाय को सशक्त बनाते हैं।

इंटर्नशिप कितनी जरूरी है?

समर इंटर्नशिप करियर के बारे में आपका नजरिया बदल सकती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक छात्रा ने हमसे कहा कि आर्ट और कलर उसकी जिंदगी है। वह आर्टिस्ट बनना चाहती थी लेकिन स्टूडियो में इंटर्नशिप के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह मार्केट और आर्ट की सेल के बारे में कहीं अधिक इच्छुक थी। इसलिए आखिर में उसने मैनेजमेंट कोर्स जॉइन कर लिया।

सही यूनिवर्सिटी का चुनाव कैसे करना चाहिए?

सही चॉइस ही आपको सही नौकरी, सही करियर, सही माहौल और यहां तक कि सही पार्टनर तक पहुंचाती है। इसलिए तमाम संभावनाओं पर विचार करने के बाद ही तय करें कि आप सबसे अधिक कहां फिट बैठते हैं। भारत में पैरेंट्स अपनी आय का 70 प्रतिशत हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। मगर जब कोई स्टूडेंट चार साल यूनिवर्सिटी में बिताता है, तो हमें खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या वह वहां खुश है!

स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (एसओपी) में यूनिवर्सिटी क्या देखती है?

एसओपी में यूनिवर्सिटी आपके बारे में ज्यादा जानना चाहती है। ऐसा अमेरिका व ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में खास तौर पर होता है। मैं सलाह देती हूं कि एसओपी खुद तैयार करें। इसके लिए किसी और को हायर न करें।

आपके सपनों को साकार करने का मौका

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के साथ आपके सपनों को साकार करने का मौका देगा। इस क्षेत्र में एयरोस्पेस इंजीनियर का मुख्य काम एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, उपग्रह और मिसाइलों को डिजाइन करना है। साथ ही सभी डिजाइन का सही आकलन करने के लिए उनके प्रोटोटाइप का परीक्षण करते हैं। इसके अलावा ये निर्धारित योजनाओं के अनुकूल कार्य भी करते हैं।

अगर आप बचपन में आसमान में उड़ते प्लेन को देखकर उत्साहित हो जाते थे और अब भी नीले आसमान में उड़ान भरने के साथ अंतरिक्ष का सैर करना चाहते हैं तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग आपके लिए एकदम सही करियर विकल्प है। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग आपको अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने के साथ आपके सपनों को साकार करने का मौका देगा। इस क्षेत्र में एयरोस्पेस इंजीनियर का मुख्य काम एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, उपग्रह और मिसाइलों को डिजाइन करना है। साथ ही सभी डिजाइन का सही आकलन करने के लिए उनके प्रोटोटाइप का परीक्षण करते हैं। इसके अलावा ये निर्धारित योजनाओं के अनुकूल कार्य भी करते हैं।

इन कार्यों के अलावा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले इंजीनियर एयर क्राफ्ट की ताकत उसकी क्षमता, विश्वसनीयता और विमान तथा उसके अन्य पार्ट्स का लम्बे समय तक टिकाऊ बने रहने के लिए ध्वंसात्मक तथा गैर ध्वंसात्मक परीक्षण की दिशा में कार्य कर सकते हैं या फिर कार्य करने के लिए निर्देश दे सकते हैं।

एयरोस्पेस इंजीनियर का कार्य

इस क्षेत्र में एयरोस्पेस इंजीनियर का कार्य स्पेसक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम और एविएशन और एविओनिक्स में इस्तेमाल होने वाली नई इंजीनियरिंग तकनीकों को तैयार करना है। इसके अलावा एक एयरोस्पेस इंजीनियर वायुगतिकीय द्रव प्रवाह जैसे क्षेत्रों में कुशल होता है। जैसे- संरचनात्मक डिजाइनय मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण इंस्ट्रूमेंटेशन और संचार, रोबोटिक्स, या प्रणोदन और दहन आदि। साथ ही वे विभिन्न प्रकार के एयरोस्पेस मशीनरी को डिजाइन करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धक विमान अंतरिक्ष यान, उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, रॉकेट और मिसाइल।

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए एजुकेशन

अगर आप एयरोस्पेस में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम स्नातक की डिग्री यानी बीई या फिर बीटेक व बीएस या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री उन उम्मीदवारों के लिए एक 4 वर्ष का कार्यक्रम है, जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी की है। टफ मैथ्स और कम्प्यूटेशनल फार्मूलों के साथ भौतिकी की गतिशीलता को समझना एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए कुछ आवश्यक लक्षण हैं। वहीं एमएसए एमटेक और पीएचडी आदि विश्वविद्यालयों जैसे स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निबंध परीक्षा और व्यक्तित्व साक्षात्कार के बाद मानकीकृत परीक्षा में स्कोर करना जरूरी है।

क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी

एक एयरोस्पेस इंजीनियर में क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए। सीधी बात कि उनमें यह सोचने में सक्षम होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में डिजाइन, सामग्री और अंतिम उत्पाद या परियोजना विफल हो सकती है और एक गड़बड़ या विफलता के मामले में वैकल्पिक विकल्प क्या होने चाहिए।

टीम वर्कर

एक एयरोस्पेस इंजीनियर टीम में काम करता है, उसे काम के माहौल में सीखने और बनाने में सक्षम होने के लिए एक अच्छा टीम वर्कर होना चाहिए।

राइटिंग स्किल

एयरोस्पेस इंजीनियर के लिए यह बहुत जरूरी स्किल है कि उनके अंदर स्पष्ट लेखन के लिए अच्छा लेखन कौशल होना चाहिए और ऐसे डिजाइन बनाने चाहिए जो अन्य टीम के कार्यकर्ता पूरी तरह से समझ सकें।

एनालिटिकल स्किल

एयरोस्पेस मशीन के साथ विभिन्न वातावरणों के विकल्पों का सुझाव देने के लिए एयरोस्पेस मशीन और उसके डिजाइन की कार्य परिस्थितियों को समझने के लिए साउंड एनालिटिकल स्किल होने चाहिए।

बिजनेस स्किल

एयरोस्पेस इंजीनियर को यह पता होना जरूरी है कि वो जिस परियोजना में लगे हैं, उसकी लागत क्या होगी और कंपनी या सरकार को फायदा कैसे मिलेगा। क्योंकि सभी तरह के फायदे के लिए रूपरेखा एयरोस्पेस इंजीनियर को बनानी पड़ती है।

भारत में एयरोस्पेस इंजीनियर

अगर आप एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको एयरलाइंस के अलावा वायु सेना, कॉर्पोरेट रिसर्च कंपनियों, रक्षा मंत्रालय, हेलीकाप्टर कंपनियों, विमानन कंपनियों में जॉब मिल सकती है। भारत के अंदर इस क्षेत्र में प्रमुख भर्ती करने वालों में से कुछ हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नागरिक उड्डयन विभाग, एयर इंडिया, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व अन्य।

एयरोस्पेस इंजीनियर कहां काम करते हैं

इंजीनियर ज्यादातर सरकारी एजेंसियों और मेन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ चुनिंदा एयरोस्पेस इंजीनियरों को नासा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने के लिए भी चुना जाता है। वर्तमान में एयरोस्पेस इंजीनियर एयरोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। साथ ही इनके पास एयरक्राफ्ट पावर प्लांट जैसे टर्बो प्रोप, पिस्टन इंजन और जेट्स के कामकाज के विषय में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। कुछ एयरोस्पेस इंजीनियर राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर काम करते हैं और इसके लिए उन्हें सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती है।

जॉब के अवसर

इस क्षेत्र में जॉब के लिए आपके पास कम से कम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है। कई ऐसे एम्प्लॉयर जो विशेष रूप से जो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं, उन्हें एक सर्टिफाइड इंजीनियर की आवश्यकता होती है। इस समय देश में निम्नलिखित संगठन जॉब दे रहे हैं।

- एयर फोर्स
- सरकारी अनुसंधान
- कॉर्पोरेट अनुसंधान
- हेलीकॉप्टर कंपनियां
- एयरलाइंस
- एयरशिप्स
- विमानन कंपनियां
- मिसाइल
- फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट
- रक्षा मंत्रालय
- उपग्रह
- अंतरिक्ष यान

जीवन के और हमारे मन के भी दो पहलू होते हैं। हम या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। यदि हम सकारात्मक होना चुनते हैं, तो यह आशा और आत्मविश्वास जगाता है। हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। हम स्फूर्त होते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। देश और दुनिया के युवा लीडर्स इन्हीं बातों पर जोर देते हैं।

सकारात्मकता को चुनते हैं देश और दुनिया के युवा

जानी-मानी फैशन स्टाइलिस्ट है अमी पटेल। वे काजोल, तारा दत्ता, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार और ऐसे ही कई दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स के फैशन, उनके स्टाइल को मैंटेन रखने का काम करती हैं। उनके मुताबिक, स्टाइल फीका है यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा साथ नहीं दे रहा। यदि आप खुद अव्यवस्थित या कंफ्यूज रहते हैं, तो फैशन से इसे बदलना मुश्किल है। विचार आपका आईना है, यह ध्यान रखें। फिर आप जो भी पहनेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। अमी खुद एक मेडिटेशन टीचर भी हैं और सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए इसे बहुत जरूरी मानती हैं। उनके मुताबिक, हमें वह सब करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी सकारात्मक सोच को बनाए रखने में मदद मिल सके।

सीखने की ललक

जस्ट डायल के सीईओ वीएसएस मणि की सक्सेस स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। इसका सार यह है कि यदि आप विपरीत परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। वे कहते हैं, जब मैंने इस बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा था, तो भारत में इंटरनेट का इतना प्रभाव नहीं था। एक तो मुश्किल आइडिया, उस पर घर की माली हालत खराब। काम शुरू करना है, तो पैसा चाहिए ही, सो मैंने दूसरे कामों के साथ जुड़कर घर की जिम्मेदारी भी संभाली और अपने बिजनेस आइडिया पर भी चुपचाप काम करता रहा। मणि आज भी अपने बिजनेस को 20 साल पुराना स्टार्ट-अप ही कहते हैं। उनके अनुसार, इससे सीखने की ललक बनी रहती है। जब तक यह इच्छा रहेगी, आपकी सोच भी सकारात्मक रहेगी। सकारात्मक लोग हमेशा कुछ-न-कुछ करते-सीखते रहते हैं।

समस्याओं से न भागें

मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि आप तमाम जिम्मेदारियों से उपजे स्ट्रेस के बीच कुंठित क्यों नहीं होते, गुस्सा क्यों नहीं आता? मेरा जवाब होता है, आप इसके अलावा यह भी तो कह सकते हैं कि आप कितने पॉजिटिव हैं! यह कहना है ब्रैंडन वैलेस का। वे अमेरिकी सरकार में पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर कार्यरत हैं। अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के अलावा, वे युवाओं से जुड़े मसलों पर भी सक्रिय हैं। खास तौर पर इस दिशा में कि युवाओं को शांति और सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए।

वे कहते हैं, कोई समस्या आपके सामने आती है, तो दो ही विकल्प होते हैं आपके पास। या तो आप समस्याओं से जूझें, दुख-दर्द का अनुभव करें या फिर इन सबका पूर्वानुमान लगाकर पलायन कर जाएं। मैं दर्द लेता हूं क्योंकि यह हमें अंततः स्थिर करता है। हममें ठहराव लाता है और इस ठहराव का चयन हमेशा सकारात्मक मिजाज का व्यक्ति ही कर सकता है।

फोकस खुद पर

जिनकी सोच सकारात्मक होती है, वे हमेशा अपनी गलतियों की तरफ देखते हैं। उनमें सुधार के बारे में चिंतन करते हैं। वे रुकी हुई घड़ी को भी देखकर यह कहना जानते हैं कि देखो, यह घड़ी नहीं चल रही लेकिन यह रोज दो बार सही वक्त बता पाने में सक्षम है। ब्रिटेन की अभिनेत्री फागुन ठकरार बचपन से अभिनेत्री बनना चाहती थीं, पर उनके पैरेंट्स की इच्छा थी कि वे डॉक्टर बनें। वे डॉक्टर बनीं भी, मगर बाद में कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने अपना सपना भी पूरा किया। आज वे डॉक्टर ही नहीं, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और फैशन डिजाइनर भी हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी फागुन कहती हैं, मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग क्या सोचेंगे। मैं हमेशा इसका ध्यान रखती हूं कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। अपने काम के दौरान मैंने बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं। लीक से हटकर सोचना और करना आसान नहीं, लेकिन मेरे पास जादू की छड़ी है और वह है सकारात्मक सोच।

कलिंग समाचार

संपादकीय

मंगलवार 16 दिसंबर 2025

संसद में खतरनाक खेल की शुरुआत

देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेल को भाजपा अब एक खतरनाक स्तर पर ले आई है। इसे रोकना या इसका हल निकालना आसान नहीं है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण हिंदू या मुसलमान बोलकर नहीं हो रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। इस खेल में इतिहास को बदला जा रहा है, तथ्यों पर झूठ चढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह सब संस्थागत तरीके से हो रहा है। सोमवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा करना इसी का प्रमाण है। इस बार का शीतकालीन सत्र बेहद छोटा है, जिसमें कामकाज के कुछ घंटे पहले ही हंगामे में निकल चुके हैं। बचे वक्त का अच्छा इस्तेमाल देश के सामने आई बड़ी विपदाओं पर चर्चा कर उनका हल निकालने या विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर विमर्श करने में लगाया जा सकता था। एसआईआर के कारण बीएलओज़ की मौत, इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्रियों पर आई मुसीबत, दिल्ली में आतंकी हमला, प्रदूषण, रुपए की गिरती कीमत, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पेंच, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान-मजदूर हित, युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति ऐसे ढेरों मुद्दे हैं जिन पर संसद का कीमती वक्त लगना चाहिए था। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेढ़ सौ साल पहले लिखे गीत को लेकर अकारण बहसबाजी की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यह दुस्साहस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में देश को उन ताकतों से मुक्त करना है, जिनके कारण संविधान बना हुआ है। यह संविधान ही है जो देश में तानाशाही कायम नहीं होने देता। लोगों को हि मत देता है कि अगर उन्हें सरकार का कोई फैसला पसंद न आए या अपने हित खतरे में पड़ते दिखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी संविधान की दी हुई ताकत से किसानों ने एक साल लंबा आंदोलन चलाया, जिसके बाद नरेन्द्र मोदी को कृषि कानून वापस लेने पड़े। अभी संचार साथी ऐप प्रीइंस्टाल करने का फैसला हटाना पड़ा। वक्फ संशोधन अधिनियम को संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण है, जिनमें बहुमत के बावजूद मोदी सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। यही बात शायद सरकार को खटक रही है, क्योंकि इस बार तो संसद में विपक्ष पहले से अधिक ताकतवर है। ऊपर से बिहार चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए अब नरेन्द्र मोदी ने वंदे मातरम् का विवाद खड़ा कर कांग्रेस को निशाने पर लेने की एक और कोशिश की है। संसद में श्री मोदी के भाषण से यह समझ आ गया कि चर्चा शब्द का मुखौटा लगाकर भाजपा देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को बढ़ावा दे रही है, ठीक ऐसा ही काम भाजपा के पुरखों यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने किया था। आजादी की लड़ाई के लंबे कालखंड में संघ का योगदान रत्ती भर भी देखने नहीं मिलता है। बल्कि इस बात के सबूत हैं कि वी डी सावरकर ने सजा से बचने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी और उनकी सेवा करने का वचन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त भी संघ के लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी कर रहे थे और जनता को अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए उकसा रहे थे। लेकिन आज उसी संघ से निकले नरेन्द्र मोदी कांग्रेस पर देश विभाजन का आरोप लगा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम् के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोह मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम् के खिलाफ नारा बुलंद किया था। इसको लेकर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् के 100 साल हुए थे, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। लगभग एक घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री ने 13 बार कांग्रेस और 7 बार नेहरू का नाम लिया। श्री मोदी ने पं.नेहरू को मुस्लिम लीग के आगे झुकता बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि 1937 में ब्रिटिश इंडिया में कुल 11 राज्य थे, तब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकार बनाई।

मुश्किल मुद्दों की वजह से मणिपुर समस्या के समाधान में हो रही है देरी

रवींद्र नाथ सिन्हा

मणिपुर का पूरा इलाका- पहाड़ियां और घाटियां दोनों- हमेशा मणिपुर के राजाओं, राज्य दरबार और बाद में, राज्य सरकार के प्रशासन में था। मैनेजमेंट के नियमों (1907) ने साफ तौर पर दरबार को दोनों इलाकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया, जो ज़मीन, जंगल और टैक्स का प्रबंधन करता था। ब्रिटिश अधिकारी नियमित तौर पर यह रिकॉर्ड करते थे कि जंगल और इलाके महाराजा की संपदा थे। हालात के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया, जो बदलते रहते हैं, ने मणिपुर में बदलते घटनाक्रम में जातीय संघर्ष की कहानी को अलग करते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 6 और 7 नवंबर को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) के दायरे में आने वाले 24 विद्रोही गुटों में दो बड़े गुट हैं। दो दिनों तक चली बातचीत को केन्द्रीय गृह मंत्रालय और एक तरह से पहचाने जाने वाले% 24 कुकी- ज़ो विद्रोही गुटों के बीच एक अहम बातचीत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली 4 सितंबर को जो बातचीत हुई थी, उसके बाद बंद पड़े एसओओ को फिर से सक्रिय किया गया था, जिससे मैतेई सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशन (सीएसओ संगठन) बहुत नाराज़ थे, जो एसओओ की उस अवधारणा के ही खिलाफ हैं जिसे 2008 में लाया गया था।

फिर से एसओओ को सक्रिय करने के समझौते में नई शर्तें हैं, जिनमें संविधान के अंदर समझौता, इलाके की अखंडता का भरोसा, कैडर की जांच और पुष्टि, विदेशी नागरिकों को वापस उनके देशों में भेजना और शिविरों को फिर से अन्यत्र ले जाना शामिल हैं। एसओओ में पहले से तय समय पर और आगे बढ़ाने का प्रावधान था। हालांकि, 29 फरवरी, 2024 को, यानी 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा शुरू होने के 10 महीने बाद और जब मणिपुर की कानून-व्यवस्था की हालत सबसे खराब थी, तब के मु यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने तीन-तरफ़ा एसओओ से यह कहते हुए बाहर निकलने का फैसला किया कि इसके दायरे में आने वाले ग्रुप ज़मीनी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

यह बताना ज़रूरी है कि 3 मई, 2023 से पहले, ये ग्रुप संविधान के छठे शेड्यूल के तहत स्वायत्त क्षेत्र परिषद (ऑटोनॉमसटेरिटोरियल काउंसिल) की मांग कर रहे थे। हिंसा बढ़ने और बेघर हुए लोगों की सं या बढ़ने के बाद, उन्होंने पहाड़ी इलाकों के लिए विधायिका से केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठानी शुरू कर दी। जैसा कि इस लेख के शुरू में ही बताया गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया मणिपुर आ यान के हिस्से हैं। अब मैतेई सीएसओ की बारी थी कि वे प्रतिक्रिया करें और पिछली ज़मीनी हकीकत का अपना संस्करण पेश करें और उसके समर्थन में ऐतिहासिक काल खंडों, संबंधित नियम और न्यायालयों के फैसले% का हवाला दें। 17 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री को लिखे एक ज्ञापन में, जिसकी प्रतिलिपियां केंद्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सलाहकार (नॉर्थ-ईस्ट) ए के मिश्रा को भी भेजी गई हैं, मणिपुर एकता और अखंडता पर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (कोकोमी) ने कहा है- यह कहना कि मणिपुर के पहाड़ी इलाके कभी भी मणिपुर के महाराजा के शासन में नहीं थे, ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों को जानबूझ कर गलत तरीके से पेश करना है% जिसका मकसद एक अलग कुकी प्रशासनिक क्षेत्र की मांग को सही ठहराना है। इसके उलट, पुराने रिकॉर्ड, मणिपुर स्टेट दरबार रूल्स (1907) और आज़ादी के बाद अदालतों के फैसले (जो 1963 और 1979 में आये थे) ने इस बात की पुष्टि की कि पूरा इलाका, जिसमें पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं, राज्य और उसके बाद आने वाले शासकों के लगातार कानूनी अधिकार क्षेत्र में रहा।

यह एक सोच-समझकर बनाई गई ब्रिटिश औपनिवेशिक सीमावर्ती नीति (कॉलोनियल फ्रंटियर स्ट्रैटेजी) का नतीजा था, जिसे अस्थिर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस भूराजनीतिक इंजीनियरिंग में एक अहम भूमिका मणिपुर में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट (1844-1863) लेि टनेंट-कर्नल विलियम मैकुलोच ने निभाई थी। बसाया गया जो धीरे-धीरे गांव बन गए। इन तीन मकसदों को पूरा करने के लिए ये इलाके बनाए गए थे- लुशाई पहाड़ियों से होने वाले हमलों के खिलाफ एक ह्यूमन बफ़र ज़ोन बनाना, ज़मीन को राजस्व कमाने वाली खेती के इस्तेमाल के तहत लाना और लोगों को मज़दूरी और सहायक सेना के स्रोत के तौर पर काम पर रखना।

कुकी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से उन इलाकों में बसाया गया जो धीरे-धीरे गांव बन गए। इन तीन मकसदों को पूरा करने के लिए ये इलाके बनाए गए थे- लुशाई पहाड़ियों से होने वाले हमलों के खिलाफ एक ह्यूमन बफ़र ज़ोन बनाना, ज़मीन को राजस्व कमाने वाली खेती के इस्तेमाल के तहत लाना और लोगों को मज़दूरी और सहायक सेना के स्रोत के तौर पर काम पर रखना। 19वीं सदी के बीच की यह घटना, कोकोमी के कन्वीनरखुरैजमअथौबा के हस्ताक्षरित किए हुए प्रधानमंत्री को भेजे मांगपत्र में बताया गया है कि यह घटना %एक हज़ार साल से भी ज़्यादा समय से मैतेई और दूसरे आदिवासी पहाड़ी समुदायों के लगातार और अच्छी तरह से रहने% के दस्तावेज से बिल्कुल अलग है। अथौबा ने यह भी कहा है कि कुकी शब्द एक औपनिवेशिक बनावट है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए चिन-लुशाई पहाड़ियों और कुकी लोगों के स्वदेशी होने और पुरखों के ज़मीन के अधिकारों के दावों को खारिज कर देना चाहिए, जो ऐतिहासिक नहीं% हैं और मणिपुर राज्य की कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता के खिलाफ हैं। कोकोमी ने तर्क दिया है कि उनकी मांग मानना राज्य के मूल निवासियों की क्षेत्रीय अखंडता और कानूनी अधिकारों को कमज़ोर करने जैसा होगा।

(1824-1826) में ब्रिटिश जीत के बाद लगभग 1840 में पहाड़ी इलाकों में कुकी प्रव्रजन शुरू हुआ। यह एक सोच-समझकर बनाई गई ब्रिटिश औपनिवेशिक सीमावर्ती नीति (कॉलोनियल फ्रंटियर स्ट्रैटेजी) का नतीजा था, जिसे अस्थिर पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस भूराजनीतिक इंजीनियरिंग में एक अहम भूमिका मणिपुर में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट (1844-1863) लेि टनेंट-कर्नल विलियम मैकुलोच ने निभाई थी।

मणिपुर का पूरा इलाका- पहाड़ियां और घाटियां दोनों- हमेशा मणिपुर के राजाओं, राज्य दरबार और बाद में, राज्य सरकार के प्रशासन में था। मैनेजमेंट के नियमों (1907) ने साफ तौर पर दरबार को दोनों इलाकों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाया, जो ज़मीन, जंगल और टैक्स का प्रबंधन करता था। ब्रिटिश अधिकारी नियमित तौर पर यह रिकॉर्ड करते थे कि जंगल और इलाके महाराजा की संपदा थे। मणिपुर के भारत में शामिल होने पर, ऐसी सभी ज़मीनों का मालिकाना हक कानूनी तौर पर राज्य सरकार के पास आ गया। इस निरंतरता को भारत के संविधान की धारा 372, पार्ट सी स्टेट्स लॉज़ एक्ट (1949) और मर्ज्ड स्टेट्स लॉज़ एक्ट (194) ने सुरक्षित रखा। मणिपुर उच्च न्यायालय (1963) और गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1979) ने कानूनी ढांचे को सही ठहराया था। इसलिए, केंद्र सरकार को कुकी लोगों के स्वदेशी होने और पुरखों के ज़मीन के अधिकारों के दावों को खारिज कर देना चाहिए, जो ऐतिहासिक नहीं% हैं और मणिपुर राज्य की कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता के खिलाफ हैं। कोकोमी ने तर्क दिया है कि उनकी मांग मानना राज्य के मूल निवासियों की क्षेत्रीय अखंडता और कानूनी अधिकारों को कमज़ोर करने जैसा होगा।

मोदी को उलटा पड़ा वंदे मातरम् पर बहस का दांव

अनिल जैन

लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से मोदी और उनकी पार्टी को यह भी बताया कि वंदे मातरम् के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत बनाने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पांच लोगों की एक समिति ने लिया था जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद शामिल थे। राष्ट्रीय गीत %वंदे मातर % की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार की पहल पर संसद के दोनों सदनों में एक-एक दिन की विशेष बहस का आयोजन हुआ। सब जानते हैं कि यह गीत हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान रचा गया था और यह देश भर में, खासकर बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के अधिवेशनों में भी यह गीत गाया जाता था और देश आजाद होने के बाद इसे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में भी मान्यता दी। इसलिए इस पर चर्चा बहस करने-कराने का कोई औचित्य नहीं था। हां, इसके 150 वर्ष पूरे होने पर संसदीय बहस से इतर कोई कार्यक्रम जरूर हो सकता था, लेकिन सरकार का मकसद इस पर बहस के जरिये राजनीतिक लक्ष्य को साधना था, सो उसने तमाम ज्वलंत और जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर वंदे मातरम् पर बहस कराई।

देश में पिछले कुछ दिनों से कई तरह के विवादों से घिरे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के चलते अब तक 45 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ सहित 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये की दुर्दशा के रोज नये रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली सहित समूचा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रदूषण की मार से गैस चैंबर बना हुआ है, जिससे लाखों लोगों के फेफड़े सड़ गए हैं। देश के तमाम हवाई अड्डों पर पांच दिन तक अफरा-तफरी मची रही और लाखों लोग परेशान हुए। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोग जिंदा जल मरे; लेकिन इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए देश की संसद में बहस हुई वंदे मातरम् पर।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी-भरकम जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर है, जहां आगामी मार्च-अप्रैल में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में चुनाव से पहले भी भाजपा के गठबंधन की सरकार थी और वहां उसे मिली जीत पर कई सवाल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का मैदान उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। उस चुनौती को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग तो अपने काम में जुटा ही है और मोदी भी अपने अभियान जुट गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने शुरुआत संसद से की है और मुद्दा बनाया वंदे मातरम् को।

अपने राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल करने में नरेन्द्र मोदी का कोई सानी नहीं है। चूंकि वंदे मातरम् की रचना बंगाल की धरती पर हुई थी और उसके रचयिता थे बंगाल के कवि-उपन्यासकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय। उनके पांच छंदों वाले इस गीत के पहले दो छंदों को ही भारत के संविधान निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को उ मीद थी कि वे संसद में बहस के दौरान इस गीत में कांट-छांट करने के लिए विपक्ष की, खास तौर पर कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए अपनी पार्टी को देशभक्त और बांग्ला अस्मिता का पहरुआ साबित कर सकेंगे। लोकसभा में बहस की शुरूआत करते हुए मोदी और उनकी पार्टी ने यही करने की भरपूर कोशिश की लेकिन उनका यह दांव पूरी तरह उलटा पड़ गया।

नरेन्द्र मोदी वैसे तो अपने सभी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को अपने से दोयम मानते हैं और ऐसा वे समय-समय पर परोक्ष रूप से जताने की कोशिश भी करते हैं, परन्तु देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू से तो उन्हें स त नफरत है, जिसे वे खुलकर व्यक्त करने में कोई कोताही नहीं करते। वंदे मातरम् पर बहस के दौरान भी इतिहास संबंधी अपने अधकचरे ज्ञान का परिचय देते हुए उन्होंने नेहरू और कांग्रेस को निशाना बनाया और खूब अनर्गल आरोप लगाए। उन्हीं की देखा-देखी उनकी पार्टी के दूसरे वक्ताओं ने भी ऐसा ही किया।

दरअसल इतिहास संबंधी किसी भी मुद्दे पर बोलते वक्त मोदी को ऐतिहासिक तथ्यों से कोई मतलब नहीं रहता। चूंकि मीडिया लगभग पूरी तरह उनके ताबे में है, इसलिए उनसे कभी कोई सवाल नहीं करता है। सत्ता के बल पर अनैतिक तरीके से हासिल इस सुविधा का वे भरपूर फायदा उठाते हुए जो मन में आता है, बोल देते हैं। ऐसा ही उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी करते हैं।

वंदे मातरम् पर बहस के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया। संभवतः विपक्षी नेताओं को मोदी के ऐसा करने का अंदाजा था, इसलिए वे पूरी तैयारी से सदन में आए थे। विपक्ष की ओर से तरुण गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, ए. राजा, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, असदउद्दीन ओवैसी आदि वक्ताओं ने ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों के जरिये प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं के तथ्यहीन भाषणों के धुर्रे बिखेर दिए। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस बार भी जोरदार तरीके से हुआ। अपनी पार्टी को देशभक्ति का अकेला झंडाबरदार साबित करने के चक्कर में मोदी और भाजपा के दूसरे नेता अपने राजनीतिक और वैचारिक पुरखों के पापों का पिटारा खुलवा बैठे। विपक्षी वक्ताओं ने मोदी को याद दिलाया कि देश की आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ब्रिटिश हुकूमत के सहयोगी बने हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस समय विभिन्न धाराओं के लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले लाठी-गोली खा रहे थे तब आरएसएस और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों की फौज में भारतीयों को भर्ती करने का अभियान चला रखा था और डेढ़ लाख भारतीयों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराया था।

विपक्षी वक्ताओं ने मोदी और उनकी पार्टी को यह भी याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सावरकर की हिंदू महासभा जिन्नाह की मुस्लिम लीग के साथ तीन प्रांतों- बंगाल, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में साझा सरकार का हिस्सा बनी हुई थी। मोदी को यह भी याद दिलाया गया कि आरएसएस ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार किया था और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन% को ब्रिटिश शासक की स्तुति में लिखा हुआ बताते हुए उसे राष्ट्रगान मानने से इनकार किया था।

दरअसल मोदी और उनकी पार्टी को महात्मा गांधी और नेहरू का इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान या आजादी के बाद भी कभी आरएसएस और हिंदू महासभा के नेताओं को गद्दार या देशद्रोही नहीं कहा। वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे और लोग उन पर भरोसा भी कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आरएसएस और भाजपा के लिए उस टैग को अपने गले से हटा पाना आज तक मुश्किल होता। लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से मोदी और उनकी पार्टी को यह भी बताया कि वंदे मातरम् के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत बनाने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पांच लोगों की एक समिति ने लिया था जिसमें रवींद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद शामिल थे। मोदी को यह भी याद दिलाया गया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1936 में वंदे मातरम् का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह नारा लगाने वाले को कोड़ों की सजा दी जाती थी। मोदी से पूछा गया कि वे बताएं कि आरएसएस और हिंदू महासभा के कितने लोग वंदे मातरम् का नारा लगाते हुए जेल गए थे और उन्होंने सजा भुगती थी? पूरी बहस के दौरान स्पीकर ओम बिड़ला की निष्पक्षता का पलड़ा हमेशा की तरह सत्ता पक्ष की तरफ़ ही झुका रहा। प्रधानमंत्री सहित सत्ता पक्ष के हर वक्ता के भाषण को उन्होंने मुग्ध भाव से सुना लेकिन विपक्ष के लगभग हर वक्ता के भाषण के दौरान उन्होंने टोका-टाकी करते हुए उनके भाषण की लय को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बावजूद विपक्षी वक्ता तथ्यों और तर्कों के जरिये सत्ता पक्ष को बगलें झांकने के लिए मजबूर करने में सफल रहे। कुल मिलाकर आम बोल-चाल की भाषा में कहें तो वंदे मातरम् पर बहस में सरकार को लेने के देने पड़ गए। कहावत है कि मियांजी गए थे नमाज़ अदा करने लेकिन रोज़े गले पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी ऐसा ही हुआ।

विविध समाचार

परिसीमन की प्रक्रिया आरक्षित आदिवासी, दलित सीट कम करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है-सोरेन

रांची १५/१२ (संवाददाता): झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया एक सुनियोजित 'साजिश' और 'छिपे एजेंडे' के तहत लायी जा रही है ताकि आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम किया जा सके।

सोरेन ने विधानसभा में यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता केवल राज्य और देश के विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। बजट सत्र के आखिरी दिन सोरेन ने कहा, ''परिसीमन की कवायद के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है, जो है आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीटों को कम करना। पहले भी ऐसी कोशिशें की गई थीं, जिन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने विफल कर दिया था। लेकिन इस बार इसे पूरे देश के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत आगे लाया जा रहा है।''

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या की निंदा की और कहा कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को बज़्शा नहीं जाएगा। सोरेन ने कहा, ''घटना कल हुई, मैं इसकी निंदा करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने आज मृतक के परिजन से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को बज़्शा नहीं जाएगा।''मुज़्यमंत्री के भाषण से पहले भाजपा के विधायकों ने सदन बहिगर्मन वाकआउट। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुज़्यमंत्री सोरेन ने कहा कि उनके नेता केवल राज्य और देश के सर्वांगीण विकास के बारे में बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया, ''उनका एकमात्र लक्ष्य सज़ा हथियाना है, भले ही उन्हें जनादेश न मिले। इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक राज्यों में उनकी सरकार हो, ताकि वे देश के वर्तमान संविधान को बदल सकें। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने विज़ीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सामाजिक सुरक्षा पर रहा है। उन्होंने कहा, ''सरकार करीब 58 लाख महिलाओं को मईया सज़्मान योजना का लाभ दे रही है। योजना का असर एक-दो साल में दिखने लगेगा। सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सोरेन ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह दिल्ली समेत कई राज्यों में महिलाओं को मइया सज़्मान जैसी योजना देने का वादा करके सज़ा में आई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनाथ और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, ''हम जल्द ही वाल्मीकि छात्रवृज़ि योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत ऐसे छात्रों को दैनिक जरूरतों, अध्ययन सामग्री और अन्य खर्चों के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे।'' सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने की भी तैयारी कर रही है।

मुज़्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा, ''हमें केंद्र से हमारा बकाया नहीं मिल रहा है। विभिन्न कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा, मनरेगा में 1,200 करोड़ रुपये और पेयजल योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये से अधिक केंद्र के पास लंबित हैं।'' विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी को शुरू हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बृहस्पतिवार को विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

झारखंड में जंगली हाथियों के हमले में महिला समेत दो की मौत

सिमडेगा१५/१२ (संवाददाता): झारखंड के सिमडेगा जिले में शुक्रवार को अलग-अलग घटनाओं में जंगली हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने यह जानकारी दी। वन अधिकारी ने बताया कि महाबुआंग पुलिस थाना अंतर्गत बुरुइर्गी देबाटोली गांव में शुक्रवार देर रात करीब एक बजे अपने घर के बाहर सो रहे 28 वर्षीय विकास ओहदार नामक व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सिमडेगा के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) शशांक शेखर सिंह ने बताया कि दूसरी घटना बानो थाना क्षेत्र के जामंग गांव में सुबह करीब छह बजे हुई। यहां पास के जंगल में महुआ के फूल एकत्र करने गई सिबिरया लुगुन नामक 45 वर्षीय महिला को हाथी ने हमला कर मार डाला।वन विभाग ने मृतक के परिजनों को तत्काल राहत के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए। अधिकारी ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मुआवजे की शेष राशि परिजनों को प्रदान की जाएगी। हाथी के हमले में जान गवाने वालों को झारखंड सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा देती है।

डबल इंजन वाले राज्यों में अपराधों की संख्या अधिक, गृह मंत्री नहीं दे रहे जवाब, आप नेता संजय सिंह का दावा

नयी दिल्ली १५/१२ (संवाददाता): राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 10 गुना अधिक अपराध हैंए यहाँ अपराध चरम पर है लेकिन आपने ;गृह मंत्री अमित शाहद्ध इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के लोग पूरे देश में नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। विनाशकारी राजनीति से इस देश को ज़्या लाभ मिल रहा हैघ् इन सब से देश के लोगों को कितना रोजगार मिला है? इससे पहले राज्यसभा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया कि ष्डबल इंजन की सरकारों वालेष् राज्यों में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिज़्मेदारी और जवाबदेही बनती है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुयी चर्चा में भाग लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज देश के अधिकतर राज्यों में ष्डबल इंजनष् की सरकार है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैंए लोगों से कहते हैं कि वे ष्डबल इंजनष् की सरकार बनाएं। सिंह ने कहा कि इसलिए देश में सुरक्षा के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिज़्मेदारी और जवाबदेही है। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध ज़्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ष्डबल इंजन की सरकारष् वाले राज्यों में होने वाले अपराधों की संज़्या की तुलना उन राज्यों से करके देख लीजिए जहां ऐसी सरकारें नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इस तुलना से पता चल जाएगा कि अपराध कहां अधिक होते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के अपराध आंकड़ों की तुलना हरियाणा से कर लीजिए जहां की आबादी पंजाब से कम है किंतु फिर भी अपराध अधिक होते हैं। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि कानून और व्यवस्था का जिज़्मा संविधान ने राज्यों पर रखा है। आज कई अपराध एक राज्य की सीमा में नहींए अंतर्राज्यीय होते हैं। नारकोटिज़्सए साइबर क्राइमए संगठित अपराध के गैंग। कई अपराध देश की सीमा से बाहर से कई अपराध किए जाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

मैं फिर कहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नज़्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।

भाजपा विधायक ने की एक गलती और आग बबूला हो गए स्पीकर, दे डाली चेतावनी

रांची १५/१२ (संवाददाता): झारखंड विधानसभा में शून्यकाल के दौरान पांकी के भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने आसन पर पक्षपात का आरोप लगाया। विरोध में सूचना से संबंधित कागज फाड़ दिया। आसन पर विपक्ष को समय नहीं देने का आरोप लगायाए इस पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो नाराज हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसन को कमजोर नहीं समझें।

दरअसलए विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता शून्यकाल के दौरान अपना प्रश्न पढ़ रहे थे। पढ़ते वक्त वे कुछ देर रुक गए। दो.तीन सेकेंड इंतजार करने के बाद स्पीकर ने कहा कि आपके प्रश्न को पढ़ा हुआ मान लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसी दौरान टुंडी के झामुमो विधायक मथुरा महतो को अपनी सूचना पढ़ने के लिए बोलाए जिसके बाद वे खड़े भी हो गए। इसपर मेहता नाराज हो गए। आसन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे ज़्यों रात में 12 बजे शून्यकाल के लिए प्रश्न डालते हैं और यहां आकर बैठते हैंए जब पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं दिया जाता। इसके बाद अपनी सूचना को फाड़ दिया।

संसदीय कार्यमंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस पर कहा कि नियमानुसार प्रश्नकाल का प्रश्न 50 शज़्द से अधिक नहीं होना चाहिएए लेकिन हम लंबा सवाल भी पढ़ते हैं। इसके बावजूद स्पीकर पूरी बात रखने देते हैं। सदन में इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के विधायकों से ऐसा व्यवहार नहीं करने का आग्रह किया। हटिया के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में कहा कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी में हेल्थ सेंटर की जमीन पर जलमीनार बनाया जा रहा है। यह जमीन हेल्थ सेंटर के लिए है। इसे आवास बोर्ड ने जुडको को दे दिया है। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने पर प्रशासन ने कई लोगों पर झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी है। उन्होंने जलमीनार दूसरी जगह बनाने का आग्रह किया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ग्रामीण पथ पर भारी वाहनों के दबाव के मामले में सरकार ट्रैफ़िक सेंसस कराएगीए उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। मंत्री भाजपा के बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के सवालों का जवाब दे रहे थे। विधायक रोशन लाल चौधरी ने पतरातू.रांची मुज़्य पथ पर नलकारी मोड़ से हरिहरपुरए सुथरपुर तथा जिंदल मुज़्य पथ भाया सलगोए सुथरपुर होते हुए मंदरो चौक कुच्चू ओरमांझी तक की ग्रामीण सड़क का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस पथ पर भारी वाहनों का आवागमन होता हैए जिससे यह सड़क जर्जर हो चुकी है। उन्होंने इस पथ के सौंदर्यीकरण की मांग की थी।

पलामू पुलिस ने कोढ़ा गैंग के 5 अपराधियों को पकड़ा

पलामू १५/१२ (संवाददाता): झारखंड के पलामू जिले की पुलिस को बड़ी सफ़लता मिली है। पुलिस ने कोढ़ा गैंग के 3 अपराधियों को गिरज़्तार किया है। इनकी मदद करने के आरोप में 2 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए अपराधियों में से 2 बिहार के रहने वाले हैं। वहीं 1 अपराधी छज़ीसगढ़ का रहने वाला है। स्थानीय लोगों में 1 महिला और 1 पुरुष हैं। यह सभी बिहार के कटिहार के कोढ़ा गांव के रहने वाले गिरोह के सरगना वासुदेव नट के लिए काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 फर्ज़ी नंबर प्लेट लगी बाइक तथा 37 पुड़िया खुजली का पाउडर बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक पलामू चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में से एक कोढ़ा गैंग के सरगना वासुदेव नट का दामाद है। गिरोह का सरगना लूट की घटनाओं के लिए बिहार तथा छज़ीसगढ़ से अपराधियों तथा अपने रिश्तेदारों को बुलाता है। यह सभी लोग अलग.अलग जिलों में रहकर पहले रेकी करते हैं। इसके आधार पर घटनाओं को अंजाम देते हैं। पलामू में भी इसी पैटर्न पर काम चल रहा था। इस काम में 2 स्थानीय लोग इनकी मदद कर रही थे। गिरोह के सरगना का इन लोगों के यहां लगातार आना.जाना लगा रहता था। बताया गया कि इस गिरोह के लोग बैंक से रुपए निकाल कर जाने वालों का पीछा करते है। इसके बाद अपने साथियों के सहयोग से उसका रुपया छीन लेते है। इसमें रेकी करनेए पीछा करने एवं खुजली पाउडर डालने वाला टीम 1 बाइक पर तथा रुपये की छिनतई करने वाली टीम दूसरे बाइक पर रहती है। घटना के समय आपस में बातचीत करने के लिए सभी लोग फर्ज़ी सिमकार्ड का इस्तेमाल करते है। वारदात को अंजाम देने के बाद मोबाइल को बंद कर देते हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक बिहार से चोरी कर लाई जाती है। पलामू में दिसंबर माह में एक के बाद एक दो वारदातों को अंजाम दिया गया। ज़्ज़्टकी मदद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसमें यह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

पकड़े गए तीनों अपराधी 1 माह पहले ही पलामू आए थे। वहीं 1 अपराधी छज़ीसगढ़ का रहने वाला है। स्थानीय लोगों में 1 महिला और 1 पुरुष हैं। यह सभी बिहार के कटिहार के कोढ़ा गांव के रहने वाले गिरोह के सरगना वासुदेव नट के लिए काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 फर्ज़ी नंबर प्लेट लगी बाइक तथा 37 पुड़िया खुजली का पाउडर बरामद किया है।

सीयूजे की जमीन, बिजली, पानी और रास्ते की परेशानियां शीघ्र दूर करें

रांची १५/१२ (संवाददाता): अपनी स्थापना के 12 वर्ष बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ;सीयूजेद्ध की जमीन का मामला हल नहीं हो पाया है। बिजली की समस्या जस की तस है। पानी की किल्लत है। यहां तक कि सीयूजे कैंपस में जाने के लिए उपयुक्त रास्ता तक नहीं। सोमवार को इन चारों विषयों पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परेशानियों को शीघ्र दूर किया जाए। राजकीय अतिथिशाला में हुई बैठक के बाद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि सीयूजे को कुल 500 एकड़ जमीन देनी थीए पर अब तक उसे 319 एकड़ जमीन दी गई है। इनमें से अधिकतर गैर मजरुआ जमीन है। इसमें से 100 एकड़ जमीन की गलत रूप से बंदोबस्ती की जा चुकी है। इसमें कुछ रैयती जमीन भी हैए जिसके कारण विरोध हो रहा है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, मंगलवार 16 दिसंबर 2025 | पृष्ठ-6

आम आदमी के लिए न्यायपालिका का मुख्य मिशन है-जस्टिस सूर्यकांत

कटक १५/१२ (संवाददाता): भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि कानून के शासन का असली मतलब तभी होता है जब न्याय अनुमानित, सुलभ और मानवीय हो। उन्होंने कहा कि जब न्याय में देरी होती है और वह महंगा हो जाता है, तो कानून के शासन का मकसद ही खत्म हो जाता है। उन्होंने नागरिकों के सामने आने वाली दो बड़ी बाधाओं-मुकदमेबाजी की ऊंची लागत और समाधान में देरी-पर ज़ोर दिया। कटक में ओडिशा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आम आदमी के लिए न्याय सुनिश्चित करन, मुकदमेबाजी की लागत और देरी को कम करने की रणनीतियाँ विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने कहा कि हर सुधार को आखिरकार अनिश्चितता को कम करना चाहिए, मुकदमों का बोझ कम करना चाहिए और गरिमा की पुष्टि करनी चाहिए। आम आदमी के लिए न्याय

सुनिश्चित करना न्यायिक प्रणाली का मुख्य मिशन होना चाहिए और अदालतों की असली परीक्षा कानूनी सिद्धांतों में नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन के अनुभव में है, उन्होंने कहा।

उन्होंने मामलों के लंबित होने को सुधार के लिए सबसे स्पष्ट शुरुआती बिंदु बताया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती जिला अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या है, जो कानून के सवालों या महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के कारण हैं, जिनके लिए ऊपरी अदालतों से स्पष्टता का इंतजार है। जब तक ऐसे मुद्दों को अंतिम रूप से हल नहीं किया जाता, ट्रायल कोर्ट जाम रहते हैं, जिससे लंबित मामलों पर इसका असर पड़ता है, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित कई श्रेणियों के मामलों को निर्णायक रूप से निपटाने की योजना बनाई है, खासकर वे जिनमें कानूनी सिद्धांतों का निपटारा शामिल है। सीजेआई ने कहा, हम मामलों को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे को पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक हल कर पाएंगे, उन्होंने कहा कि इससे हाई कोर्ट को भी उनके सामने लंबित मुद्दों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और जिला अदालतों को भी इसका फायदा होगा।

प्रणाली को स्थिर करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, जस्टिस कांत ने कहा कि जब शीर्ष अदालत कानूनी सवालों को अंतिम रूप देती है, तो निचली अदालतों को आत्मविश्वास मिलता है। उन्होंने कहा कि मामलों के भारी बैकलॉग को खत्म करने के लिए प्रभावी उपकरणों और तंत्रों की आवश्यकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को गेम-चेंजर बताते हुए, सीजेआई ने कहा कि विशेष रूप से मध्यस्थता लोकप्रिय हो रही है और अदालतों पर बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का भी आह्वान किया और कहा कि यह दूरियों को कम कर सकती है और भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकती है, लेकिन उन्होंने भोले-भाले आशावाद के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी को न्याय का सेवक बने रहना चाहिए, न कि उसका विकल्प। इसे मानवीय निर्णय को बढ़ाना चाहिए, न कि उसे बदलना चाहिए। उन्होंने सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील की कि वे अपने-अपने राज्य सरकारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों को उठाएं। उन्होंने कहा, एक ऐसा सिस्टम जहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ज्यूडिशियरी एक साथ काम नहीं करते, वह एक ऐसे तिपहिया वाहन की तरह होगा जिसका एक पहिया गायब हो और जो कानून के शासन को संतुलित करने में असमर्थ हो। अगर ये तीनों तालमेल और सहयोग से काम करते हैं, तो कई मुद्दे हल हो सकते हैं।

ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हरीश टंडन ने मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए मामलों में मुकदमे से पहले मध्यस्थता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने वकीलों से अपील की कि वे पहल करें और मध्यस्थता के ज़रिए विवादों को सुलझाएं।

आरएसपी की नई इकाइयों ने विज़ वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया

राउरकेला १५/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) की नई इकाइयों ने चालू विज़ वर्ष के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल-नवंबर, 2025-26 में अपना सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। ज़्लास्ट फर्नेस-5 (बीएफ-5) दुर्गा, देश के सबसे बड़े ऑपरेटिंग ज़्लास्ट फर्नेस में से एक, ने अप्रैल-नवंबर की अवधि में 21,33,406 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया और पिछले साल की इसी अवधि (सीपीएलवाई) में हासिल किए गए 20,33,068 टन के अपने पहले के सबसे अच्छे आंकड़े को पार करते हुए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया । ज़्लास्ट फर्नेस-1 ने भी इसी अवधि में 7,21,473 टन हॉट मेटल का अब तक का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया। अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल-2 ने सीपीएलवाई पर 4.62त्न

की वृद्धि के साथ अप्रैल-नवंबर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 17,45,714 टन एचआर कॉइल्स को रोल किया। न्यू प्लेट मिल ने पहले 8 महीनों में अपना सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा हासिल करते हुए 6,45,905 टन प्लेटों का भी उत्पादन किया।

एचएसएम-2 की शीट शियरिंग लाइन ने भी इसी अवधि के लिए अपना अब तक का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया, जो की 2,06,073 टन एचआर प्लेटों का उत्पादन किया, एवं सीपीएलवाई में 1,61,086 टन के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गया।

कई इकाइयों ने नवंबर, 2025 में व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी पंजीकृत किए। सिंटर प्लांट्स ने एक दिन का नया उत्पादन रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 28 नवंबर, 2025 को 22543 टन सिंटर का उत्पादन किया। एचएसएम-2 ने एक दिन में एक नया उत्पादन रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए 8 नवंबर, 2025 को 9822 टन एचआर कॉइल का उत्पादन करने के लिए रिकॉर्ड 10034 टन स्लैब भी रोल किया।

मयूरभंज ने ब्लैकटॉपिंग के कुछ दिनों बाद ही सड़क की सतहें उखड़ने लगी

बारीपदा १५/१२ (संवाददाता): मयूरभंज जिले के खुंटा ज़्लॉक के निवासियों ने सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है, उनका दावा है कि काम पूरा होने के मुश्किल से पांच दिन बाद ही डामर की परत उखड़ने लगी है। बड़ापठारा पंचायत के तहत चपलाडीही और बहलाडा से सपनाचुआ तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे ग्रामीण विकास विभाग के तहत उदाला डिवीजन के खुंटा सेज़्शन में लगभग 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया था, घटिया काम के कारण लोगों के गुस्से का शिकार हो गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारीपदा स्थित एक स्पेशल-ज़्लास ठेकेदार द्वारा किया गया काम जल्दबाजी में और घटिया सामग्री का उपयोग

करके, ठीक से मेटल की परत बिछाए बिना पूरा किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण के सिर्फ पांच दिन बाद ही डामर की परत उखड़ने लगी।

बताया जाता है कि बहलाडा जा रही एक बस के लौटने पर सड़क की सतह के बड़े-बड़े हिस्से उखड़ गए। पिछले हफ़्ते, निवासियों ने दिखाया कि डामर की परत को हाथ से आसानी से कैसे उठाया जा सकता है, जिससे अनियमितताएं सामने आ गईं।

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गर्म डामर के बजाय कोल्ड मिज़्स का इस्तेमाल किया गया और वाइब्रेटरी रोलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे सड़क की टिकाऊपन से समझौता हुआ। कई ग्रामीणों को विरोध में ढीला डामर हटाते और फेंकते देखा गया। निवासियों ने आगे दावा किया कि संताल साही से डाबक भुइयां साही तक नियोजित हिस्से का निर्माण बिल्कुल नहीं किया गया था। इन शिकायतों के कारण ग्रामीणों, जिसमें बड़ापठारा के सरपंच मंगल माझी भी शामिल थे, ने इस महीने की शुरुआत में जिला कलेज़्टर की जन शिकायत सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया।

इसके बाद एक जिला-स्तरीय जांच टीम ने निरीक्षण के लिए साइट का दौरा किया। अधीक्षण अभियंता सत्यब्रत नायक ने कहा कि सड़क का वह संबंधित हिस्सा जहां बिटुमेन की परत उखड़ गई थी, काम से पहले ठीक से साफ नहीं किया गया था, जिससे यह समस्या हुई। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को उस हिस्से को ठीक से दोबारा बनाने का निर्देश दिया गया है। कार्यकारी अभियंता की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि बाकी काम संतोषजनक पाया गया और आगे कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

मयूरभंज जिला कलेज़्टर हेमाकांत सोय ने कहा कि एक तकनीकी टीम और एक जिला-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। टीम में सीडीओ, एक प्रोजेज़्ट निदेशक (तकनीकी), इंजीनियरिंग विभाग का एक अधिकारी, बीडीओ और उदाला के कार्यकारी अभियंता शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्माण की गुणवज़ा की समीक्षा की। सोय ने कहा कि निर्धारित मानकों या अनुबंध की शर्तों से किसी भी विचलन से विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा जाएगा। अगर क्वालिटी खराब पाई जाती है, तो मामले की रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी जाएगी और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ठेकेदार को ज़्लैकलिस्ट करने की सिफारिश कर सकता है। काम का पेमेंट पहले ही रोक दिया गया है। हालांकि, सपंचुआ पंचायत के सरपंच लुधिया मांझी और निवासी बीरू हेंब्रम, नागेंद्र मांझी और भागीरथी गुड्डू ने कलेज़्टर के निर्देशों के बावजूद, साइट पर जाए बिना काम को संतोषजनक घोषित करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की आलोचना की। उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

मलकानगिरी में पुलिस का फ्लैग मार्च

मलकानगिरी १५/१२ (संवाददाता): हाल ही में एक महिला की हत्या के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर, जिसका सिर कटा हुआ शव पोट्टेरू नदी में मिला था, सुरक्षा बलों ने रविवार को मलकानगिरी जिले के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति काफी हद तक स्थिर हो गई है, और भाजपा सांसद बालाभद्र मांझी और स्थानीय समुदाय के नेताओं ने प्रशासन के साथ शांति और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया है। किसी भी प्रकार की नई हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने विभिन्न पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया। यह अज़्यास सुरक्षा कर्मियों की निरंतर तैनाती और एहतियाती कदम के रूप में इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन के बीच किया गया है। हिंसा प्रभावित गांवों के दौरे के दौरान, भाजपा सांसद बलभद्र मांझी ने इस घटना को घृणित बताया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा,

राखेलगुडा में हाल ही में एक हत्या हुई है। ऐसे अपराधियों को मौत की सजा से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। मांझी ने तबाही के भयावह मंजर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पास के एक गांव में लगभग सभी घर जल गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। उन्होंने आगे कहा, यह भी क्षमा के योग्य नहीं है, और राज्य सरकार से 4.5 करोड़ रुपये की घोषित राहत राशि के अलावा पर्याप्त सहायता प्रदान करने की अपील की। मलकानगिरी बंगाली समाज के अध्यक्ष गौरंगा कर्माकर ने बताया कि सांसद ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। कर्माकर ने कहा, हमारे सांसद ने हमारे गांव का दौरा किया और दोनों पक्षों को बुलाकर हमले की प्रशासनिक जांच सुनिश्चित की। यह निर्णय लिया गया कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी और आसपास के आदिवासी गांवों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि समुदाय के सदस्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहेंगे। पुलिस के मुताबिक, हत्या के मामले में मुज़्य आरोपी सुभारंजन मंडल को गिरज़्तार कर लिया गया है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द आरोपपत्र दाखिल करने के प्रयास जारी हैं। हिंसा से जुड़े दंगों के सिलसिले में छह लोगों को भी गिरज़्तार किया गया है। मलकानगिरी कलेज़्टर सोमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पिछले कई दिनों से शांति और सामान्य स्थिति बनी हुई है।

लेक्चरर की दुर्घटना में मौत, छात्रों ने प्रदर्शन कर सड़क रोकी

जगतसिंहपुर १५/१२ (संवाददाता): जिले के कुजंग इलाके में एक सड़क दुर्घटना में कुजंग कॉलेज के लेक्चरर की मौत के बाद तनाव फैल गया। गुस्साए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और बेहतर सड़क सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए कटक-पारादीप सड़क को जाम कर दिया। लेक्चरर की मौत शनिवार शाम को नेशनल हाईवे नंबर 53 पर जीरो पॉइंट के पास एक ट्रक की टक्कर से हुई थी। मलकानगिरी में पुलिस का ज़्लैग मार्च घटना के बाद, कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आए और अपने आंदोलन के तहत कटक-पारादीप सड़क को जाम कर दिया, जिससे इलाके में ट्रैफिक बाधित हो गया। रिपोर्टिंग के समय सड़क जाम हटा दिया गया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मृतक लेक्चरर के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की और उनकी पत्नी को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने चल रहे हाईवे निर्माण कार्य के कारण

इलाके में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए जीरो पॉइंट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाने की भी मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि वाहनों की भारी आवाजाही और विस्तार कार्य से उड़ने वाली धूल के कारण कम विजिबिलिटी ने इस हिस्से को बहुत अधिक दुर्घटना संभावित बना दिया है।

पोस्टमॉर्टम हाउस के पास तनाव कुजंग पोस्टमॉर्टम हाउस के पास तनाव बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने विरोध को तेज करने के लिए लेक्चरर के शव को सड़क पर लाने की कोशिश की। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को बताया कि शव केवल अंतिम संस्कार के लिए ही सौंपा जाएगा। इससे शव की कस्टडी लेने को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच कुछ देर के लिए टकराव हुआ। बाद में, पुलिस को सुरक्षा घेरे में शव को गांव के श्मशान घाट तक ले जाते समय विरोध का सामना करना पड़ा। दुर्घटना का विवरण और स्थानीय लोगों का गुस्सा रिपोर्टों के अनुसार, लेक्चरर स्कूटी से पारादीप की ओर जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे नंबर 53 पर जीरो पॉइंट के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

कुआरमुंडा ब्लॉक में आरएसपी का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न

राउरकेला १५/१२ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट कुआरमुंडा ज़्लॉक के कछारू ग्राम पंचायत के सियालजोरे गांव में संपन्न हुआ।

कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं), श्री सुदीप पाल चौधरी समापन समारोह के मुज़्य अतिथि थे जबकि मुज़्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएं एवं सीएसआर), श्री टी. जी. कानेकर सज़्मानित अतिथि थे। गणमान्य व्यक्तियों ने टूर्नामेंट के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। सरपंच, कछारू पंचायत, श्री झुबा टोप्पो, समिति सदस्य, कछारू पंचायत, श्री असविन केरकेटा, महाप्रबंधक प्रभारी

(सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बी जेना, उप प्रबंधक (सीएसआर), श्री एस के सुकुला और अन्य अधिकारी, सीएसआर के कर्मचारी, स्थानीय नेता और ग्रामीण इस अवसर पर उपस्थित थे। विशेष रूप से, तेलीपोश ग्रीन ज़्लब की टीम टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर फाइनल मैच में बेल्दीपा टीम को हराकर उभरी। इस अवसर पर श्री पाल चौधरी ने विजेताओं को बधाई दी और सभी भाग लेने वाली टीमों की भावना और उत्साह की सराहना की। उन्होंने क्षेत्र में फुटबॉल के महत्व और ग्रामीण युवाओं के बीच टीम वर्क, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में, श्री कानेकर ने आसपास के गांवों में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरएसपी की विविध सीएसआर पहलों के बारे में बात की। चैंपियंस टीम को एक ट्रॉफ़ी और 10,000 रुपये का नक़द पुरस्कार मिला, जबकि पहले उपविजेता को ट्रॉफ़ी और 8,000 रुपये का नक़द पुरस्कार मिला। लोद्सरा और लुचाबहल की टीमें तीसरे और चौथे स्थान पर रहीं, जिन्हें क्रमश: 6,000 रुपये और 4,000 रुपये का नक़द पुरस्कार मिला। आयुष मिंज को प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट के रूप में चुना गया, बिजय मिंज को सर्वश्रेष्ठ स्कोरर के रूप में चुना गया, ऑस्कर ज़ाज़्सा को सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर के रूप में चुना गया और एलेज़्स मिंज को सर्वश्रेष्ठ डिफ़ेंडर के रूप में चुना गया। इनमें से प्रत्येक को 1000/- रुपये और एक ट्रॉफ़ी से सज़्मानित किया गया।